रेल बजट 2014-15 की मुख्य विशेषताएं

मुख्य विशेष

1. संरक्षा 2. परियोजना सुपुर्दगी 3. खानपान सेवाओं एवं स्वच्छता, साफ-सफाई, शौचालयों पर ध्यान देते हुए यात्री सुविधाएं/सेवाएं 4. वित्तीय अनुशासन 5. संसाधन जुटाना 6. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल 7. पारदर्शिता एवं प्रणाली में सुधार।

रेल प्रणाली के समक्ष मुख्य चुनौतियां

- आंतरिक क्षेत्रों का बड़ा भू-भाग रेल कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा कर रहा है।
- रेलवे से वाणिज्यिक उपक्रम की तरह कमाने के साथ-साथ कल्याणकारी संगठन की तरह सेवा करने की आशा की जाती है।
- रेलें कम लागत वाली सेवाओं का वहन करके 20,000 करोड़ रु. से अधिक की सामाजिक सेवा दायिताओं को पूरा करती है। यह जीटीआर का लगभग 16.6% है और यह बजटीय संसाधनों के अंतर्गत रेलों के योजना परिव्यय का लगभग आधा बनता है।
- अधिशेष मे कमी आ रही है: अपने विकासात्मक कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।
- अपनाई गई दर निर्धारण नीति में युक्तिसंगत दृष्टिकोण की कमी रही; यात्री किराए लागत से भी कम रखे गए; प्रति यात्री किलोमीटर में हानि 2000-01 में 10 पैसे प्रति किमी. से बढ़कर 2012-13 में 23 पैसे हो गई।
- 'स्वर्णिम दुविधा का दशक' - वाणिज्यिक और सामाजिक दायित्व के बीच चयन।
- मालभाड़ा यातायात में रेलों के हिस्से में लगातार गिरावट आई।
- केवल चालू परियोजनाओं के लिए ही 5 लाख करोड़ रु. की आवश्यकता है।
- अभी तक परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के बजाय अधिक-से-अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। पिछले 30 वर्षों में 1,57,883 करोड़ रु. की 674 परियोजनाओं में से केवल 317 परियोजनाओं को ही पूरा किया जा सका। शेष परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1,82,000 करोड़ रु. की आवश्यकता है।
- अधिकांश सकल यातायात प्राप्तियों को इंधन, वेतन और पेंशन, रेलपथ एवं सवारी डिब्बा अनुरक्षण और संरक्षा कार्यों पर व्यय किया जाता है। वर्ष 2013-14 में सकल यातायात प्राप्तियां 1,39,558 करोड़ रु. थी और कुल संचालन व्यय 1,30,321 करोड़ रु. थे।
- 2007-08 में दायिता लाभांश और लीज़ प्रभारों के भुगतान के बाद अधिशेष 11,754 करोड़ रु. था और चालू वित्तीय वर्ष में 602 करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया है।

सुधार के लिए कार्रवाई एवं पहल

- क्षमता से अधिक उपयोग होने वाले नेटवर्क में दोहरीकरण और तिहरीकरण पर अधिक ध्यान देने के लिए निर्माण कार्यों की प्राथमिकता पुनः निर्धारित की जाएगी।
- लगभग 8000 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए किरायों और दर-सूची में हाल ही में हुई वृद्धि की गई।
- निम्नलिखित उपायों के जरिए वैकल्पिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता है:
  - रेलों की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में निवेश योग्य अधिशेष निधियों से रेल के सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्रों के संसाधनों का फायदा उठाना।
  - रेल अवसंरचना में घरेलू निवेश और एफडीआई।
  - सार्वजनिक निजी भागीदारी अपनाना।
- नियर प्लान हॉलीडे एप्रोच।
- चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उनकी प्राथमिकता और समय-सीमा निर्धारित करना।
- परियोजना कार्यान्वयन के लिए डिसीज़न सपोर्ट सिस्टम।
- खरीद प्रक्रिया में भागीदारी नीति एवं पारदर्शिता।
- आयातित उत्पादों के स्वदेशीकरण पर जोर।
- इंजनों, सवारी डिब्बों और वैगन लीज़िग मार्केट विकसित करना।

स्वच्छता और खानपान सहित यात्री सुविधाएं/सेवाएं एवं स्टेशन प्रबंधन

- पीपीपी माध्यम से सभी प्रमुख स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुलों, एस्केलेटरों, लिफ्ट आदि की व्यवस्था।
- रेलवे स्टेशनों पर पानी की आपूर्ति, प्लेटफार्म शेल्टरों और शौचालयों की समुचित व्यवस्था।
- सभी प्रमुख स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैटरी चालित कार।
- स्टेशनों पर यात्री सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के लिए व्यक्तियों, एनजीओ, ट्रस्टों, चेरीटेबल संस्थानों, कॉरपोरेटों को शामिल करना।
- चुनिंदा गाड़ियों में भुगतान के आधार पर वर्क स्टेशनों की व्यवस्था।
- गाड़ी, सवारी डिब्बों, बर्थ और चेयरकार की ऑन लाइन बुकिंग के दायरे को बढ़ाना।
- पार्किंग एवं प्लेटफार्म कॉम्बो टिकटें जारी करना।
- रेलवे विश्रामालयों की ई-बुकिंग।

- प्रसिद्ध ब्रांडों के रेडी-टू-ईट भोजन की व्यवस्था चरणबद्ध रूप से आरंभ करना।
- एनएबीसीबी प्रमाणित एजेंसियों द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन तंत्र आरंभ करना।
- भोजन की गुणवत्ता के संबंध में आईवीआरएस के माध्यम से फीडबैक सर्विस की शुरूआत।
- ईमेल, एसएमएस और स्मार्ट फोन आदि के माध्यम से गाड़ियों में स्थानीय व्यंजन मुहैया करवाने के लिए बड़े स्टेशनों पर फूड कोर्ट स्थापित करना। नई दिल्ली-अमृतसर तथा नई दिल्ली-जम्मू तवी के बीच इसकी पायलट परियोजना प्रारंभ करना।
- साफ-सफाई के लिए बजट आबंटन में 40% की भारी वृद्धि।
- 50 बड़े स्टेशनों पर सफाई संबंधी कार्यों की आऊटसोर्सिंग पेशेवर एजेंसियों द्वारा करना।
- स्टेशनों पर साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए अलग हाऊसकीपिंग विंग की स्थापना।
- रख-रखाव के लिए स्टेशनों पर कॉरपस फंड का सृजन।
- सफाई कार्यों की निगरानी के लिए स्टेशनों पर सीसीटीवी का इस्तेमाल।
- अखिल भारतीय स्तर पर पीआरएस टिकटों पर शिकायत/हेल्पलाइन नंबर मुद्रित करना और थर्ड पार्टी ऑडिटिंग प्रणाली शुरू करना।
- सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में ऑन बोर्ड हाऊसकीपिंग सेवाओं का विस्तार।
- एसी सवारी डिब्बों में बेहतर गुणवत्ता के बेडरोल के लिए मशीनीकृत लांड्रियों की संख्या बढ़ाना।
- स्टेशनों और गाड़ियों में प्रयोगात्मक आधार पर आरओ वाले पीने के पानी की व्यवस्था आरंभ करना।
- प्रतिष्ठित और इच्छुक एनजीओ, चेरीटेबल संस्थानों और कॉरपोरेट हाऊसों को स्टेशन गोद लेने और उनका रख-रखाव करने के लिए प्रोत्साहित करना।

संरक्षा और सुरक्षा में सुधार लाने के लिए उपाय

- ऊपरि सड़क पुलों और निचले सड़क पुलों के लिए 1,785 करोड़ रु. का प्रावधान, शीघ्रता से क्लियर करना, ऑनलाइन डिज़ाइन का मानकीकरण करना और शक्तियों का विकेन्द्रीकरण।
- बिना चौकीदार वाले समपारों को समाप्त करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण।
- टूटी हुई पटरियों का पता लगाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी- दो स्थानों पर अल्ट्रासॉनिक ब्रोकन रेल डिटेक्शन प्रणाली (यूबीआरडी) पर पटरी और वेल्डिंग की विफलताओं का पता लगाने और पायलट परीक्षणों के लिए व्हीकल बोर्न अल्ट्रासॉनिक फ्लॉ डिटेक्शन सिस्टम।
- अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप संरक्षा मानदंड। दुर्घटनाओं के कारणों के अध्ययन के लिए सिमुलेशन सेंटर।
- मेनलाइन और उपनगरीय सवारी डिब्बों में स्वत: बंद होने वाले दरवाज़ों के लिए एक पायलट परियोजना।
- 7000 रेसुब कांस्टेबलों के अलावा 4000 महिला रेसुब कांस्टेबलों की भर्ती की जानी है।

- यात्रियों को गाड़ियों में संकट के समय सहायता के लिए रेसुब मार्गरक्षी टीमों को मोबाइल फोन मुहैया कराए जाएंगे। महिला सवारी डिब्बों का मार्गरक्षण किया जाएगा। अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं पर विशेष ध्यान।
- पीपीपी माध्यम के जरिए स्टेशनों के चारों ओर बाउंड्री वॉल के निर्माण पर विचार किया जाएगा।

हरित पहलकदमियां

- स्टेशनों, रेलवे इमारतों की छतों और भूमि का उपयोग करते हुए पीपीपी माध्यम से सौर उर्जा की व्यवस्था।
- कुल डीज़ल ईंधन खपत के 5% तक बायो-डीज़ल का उपयोग।
- पटरियों और प्लेटफार्मों पर मल-मूत्र की समस्या को समाप्त करने के लिए गाड़ियों में पर्याप्त संख्या में जैविक शौचालयों की व्यवस्था करना।

रेल पर्यटन

- पूर्वोत्तर राज्यों में इको-टूरिज़्म और शैक्षिक पर्यटन।
- पहचाने गए तीर्थस्थलों के सर्किट जैसे देवी सर्किट, ज्योर्तिलिंग सर्किट, जैन सर्किट, क्रिश्चियन सर्किट, मुस्लिम/सूफ़ी सर्किट, सिख सर्किट, बौद्ध सर्किट, प्रसिद्ध मंदिर सर्किट आदि के लिए विशेष पैकेज गाड़ियां।
- कर्नाटक और महाराष्ट्र के तीर्थस्थलों और पर्यटनस्थलों को कवर करते हुए बगलकोट, बीजापुर और सोलापुर के रास्ते गदग से पंढरपुर तक पर्यटन गाड़ी।
- बेंगलूरु, चेन्नै, अयोध्या और वाराणसी जैसे तीर्थ तथा पर्यटन स्थलों को कवर करने वाली पर्यटन गाड़ी, जो रामेश्वरम से चलेगी।
- स्वामी विवेकानंद के जीवन और सेवाओं को दर्शाने वाली विशेष गाड़ी चलाना।

आरक्षण प्रणाली में सुधार सहित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल

- रेलवे आरक्षण प्रणाली को अगली पीढ़ी की ई-टिकट प्रणाली में बदलना।
- 7200 टिकटें प्रति मिनट जारी करने के लिए ई-टिकट प्रणाली जिससे 1,20,000 उपयोगकर्ता एक साथ लाभान्वित होंगे।
- सिक्के से परिचालित ऑटोमेटिक टिकट वैंडिंग मशीनें।
- इंटरनेट पर प्लेटफार्म टिकटों और अनारक्षित टिकटों की व्यवस्था।
- भारतीय रेल पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों का बड़े पैमाने पर एकीकृत रूप से कंप्यूटरीकरण किया जाएगा:-
  - भारतीय रेल पर अगले 5 वर्षों में पेपर रहित कार्यालय।
  - ए1 और ए कोटि के सभी स्टेशनों और चुनिंदा गाडियों में वाई-फाई सेवाएं।
  - गाडियों तथा चल स्टॉक की रियल टाइम ट्रेकिंग।
  - यात्रियों के लिए मोबाइल आधारित वेकअप कॉल।
  - मोबाइल आधारित गंतव्य-आगमन संबंधी चेतावनी।

- स्टेशन नेविगेशन सूचना प्रणाली।
- पीपीपी के माध्यम से सभी टिकट काउंटरों पर ड्यूअल डिसप्ले फेयर रिपीटर्स की व्यवस्था।
- स्टेशनों पर डिजिटल आरक्षण चार्ट (बेंगलूरू मॉडल)
- कंप्यूटरीकृत पार्सल प्रबंधन प्रणाली की व्यवसथा।
- निर्धारित स्टेशनों पर नामित पिक-अप सेंटरों की व्यवस्था करके विभिन्न ई-कामर्स कंपनियों को लॉजिस्टिक समर्थन उपलब्ध करवाना।
- दूर-दराज क्षेत्रों के रेल कर्मचारियों के बच्चों को रेलटेल ओएफसी (ऑप्टिकल फाइबर केबल) नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।

- रेलवे भूमि की जीआईएस मैपिंग और डिजीटाइजेशन

कर्मचारी कल्याण

- कर्मचारी हित निधि में प्रति व्यक्ति अंशदान 500 रु. से बढ़ाकर 800 रु. करना।
- रेलवे कर्मचारियों के मेधावी बच्चों के लिए विशेष प्रोत्साहन।
- सभी रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों तथा हॉस्पीटलों को एकीकृत करने के लिए हॉस्पीटल प्रबंधन सूचना प्रणाली।
- वातानुकूलित रेल इंजन केबिनों की व्यवस्था करने के लिए अध्ययन करना।

प्रशिक्षण

- तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों विषयों के लिए रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
- रेलवे से संबंधित विषयों में ग्रेजुएशन तथा कौशल विकास शुरू करने के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ समझौता।
- ग्राउंड लेवल अधिकारियों के लिए अल्प अवधि वाले पाठ्यक्रम शुरू करना ।
- उच्च गति, भारी कर्षण परिचालन इत्यादि विशिष्ट क्षेत्रों में जानकारी हासिल करने के लिए देश तथा विदेशों में स्थित संस्थानों में सभी स्तर के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को भेजना।

गाड़ियों की गति

- पहचाने गए मुंबई-अहमदाबाद क्षेत्र में बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव।
- देश के प्रमुख महानगरों तथा विकास केन्द्रों को जोड़ने वाली उच्च गति की रेल गाड़ियां चलाने के लिए हीरक चतुर्भुज की स्थापना करना और इस परियोजना को शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है।
- चुनिंदा 9 सेक्टरों में गाड़ियों की गति 160-200 किमी. प्रति घंटा तक बढ़ाना।
- प्रयोगात्मक रूप से दिए गए सभी ठहराव 30.9.2014 के बाद समाप्त हो जाएंगे।
- नए ठहरावों पर केवल परिचालनिक व्यवहार्यता तथा वाणिज्यिक औचित्य के आधार पर विचार करना; वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक रेल संपर्क पर विचार करना।

संसाधन संवर्धन

- बीओटी और वार्षिक आधार पर पीपीपी और भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर क्षमता संवर्धन के लिए 8 से 10 परियोजनाओं की पहचान; इस प्रकार की परियोजनाओं को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को पर्याप्त शक्त्यिां दी जाएंगी।
- नए तथा उदीयमान पत्त्नों के लिए पीपीपी के जरिए संपर्क स्थापित करने के लिए उपाय करना।
- महत्पूर्ण कोल कनेक्टिविटी लाइनों पर तेजी से कार्य करने से रेलवे को लगभग 100 एमटी का अधिक यातायात प्राप्त होगा और पॉवर हाऊसों के लिए कोयले का शीघ्र पारवहन सुगम होना।
- पीपीपी माध्यम से नए विकसित एयरपोर्टों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं सहित पहचाने गए स्टेशनों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकास।
- आधुनिकीकृत लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन के लिए लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना; लदान और उतराई के लिए यांत्रिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता।
- एम्पटी फ्लो से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मूल्य निर्धारण तंत्र-कम्प्यूटरीकृत एफओआईएस प्रणाली द्वारा यातायात प्रस्तुत करने वाले ग्राहकों को स्वत: छूट के लिए पायलट परियोजना।
- निजी पार्टियों द्वारा पार्सल वैनों अथवा पार्सल रैकों की खरीद को सरल बनाने के लिए योजना शुरू करना ।
- बेहतर उच्च क्षमता वाले पार्सल वैनों के नए डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- माल यातायात टर्मिनलों के नेटवर्क को विकसित करने के लिए पीपीपी मॉउल पर निजी माल यातायात टर्मिलन की स्थापना।
- सेंट्रल रेलसाइट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी करके 10 स्थानों पर फल और सब्जियों के रेल संचलन को प्रोत्साहित करना।
- रेल द्वारा दूध के पारवहन को सरल बनाने के लिए नेशनल डेयरी बोर्ड और अमूल के साथ मिलकर विशेष मिल्क टैंकर गाडियों का प्रावधान।

अन्य पहल

- संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय और परियोजना प्रबंधन के कार्य में तेजी लाने के लिए रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय स्तर पर विशेषज्ञों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर परियोजना प्रबंधन समूहों की स्थापना।
- कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों का लाभ उठाने और उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए अभिनव इनक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना।

- इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्टडी कर रहे अंडर-ग्रेजुएट छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप।
- संस्थागत सुधार - नीति निर्धारण और कार्यान्वयन की भूमिकाओं को अलग-अलग करना।
- प्रशासन और परियोजनाओं के निष्पादन में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता।
- खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तथा कारगर बनाने के लिए महत्वपूर्ण खरीद नीतियों को अपनाना।
- चालू परियोजनाओं की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध करना।
- 25 लाख रुपए एवं इससे अधिक की खरीद के लिए ई-खरीद अनिवार्य करना।
- माल डिब्बों के रजिस्ट्रेशन के भुगतान को सरल बनाने के लिए अगले दो महीने में मालडिब्बों की मांग ऑन-लाइन पर शुरू कर दी जाएगी।
- वर्ष के दौरान इलैक्ट्रॉनिक रेलवे पावती (ईआरआर) की प्रक्रिया शुरू करना।
- नमक के संचलन के लिए कम आय भार वाले जंगरोधी मालडिब्बों की शुरूआत करना।
- पूर्वी और पश्चिमी माल यातायात गलियारे के लिए समर्पित माल यातायात गलियारे परियोजना कार्यान्वयन की गहन निगरानी; सिविल निर्माण ठेकों का लगभग 1000 किलोमीटर का लक्ष्य।

महानगरीय/उपनगरीय सेवाएं

- अन्य परिवहन मंत्रालयों तथा नगर निगमों के साथ समन्वय स्थापित करके यात्री केन्द्रित परिवहन अवसंरचना पर ध्यान।
- दो वर्ष के भीतर मुंबई के लिए अतिरिक्त 864 अत्याधुनिक ईएमयू उपलब्ध कराना।
- बेंगलूरू शहर को उसके उपनगरीय तथा आंतरिक भागों से बेहतर ढंग से जोड़ने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बेंगलूरू पहुँचने के मौजूदा भारतीय रेल नेटवर्क में वृद्धि करने की संभावना तलाश करने के लिए अध्ययन।
- बेंगलूरू क्षेत्र में बय्यपनहल्ली को कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा।

वित्तीय निष्पादन 2013-14

- वर्ष 2013-14 में संशोधित अनुमान की तुलना में यातायात वृद्धि में कमी आई और खर्च में वृद्धि हुई।
- आरंभिक यात्री यातायात में 46 मिलियन की कमी; और यात्री यातायात से आमदनी में संशोधित अनुमान की तुलना में 968 करोड़ रु. की कमी हुई।
- 1,39,558 करोड़ रु. की सकल यातायात प्राप्तियां यद्यपि संशोधित अनुमान की तुलना में 942 करोड़ रु. कम थीं लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में 12.8% अधिक थीं।

- साधारण संचालन व्यय और पेंशन भुगतान संशोधित अनुमानों की तुलना में अधिक है।
- संशोधित लक्ष्य में 4,160 करोड़ रुपए की कमी दर्ज करते हुए वर्ष में 3,783 करोड़ रुपए का अधिशेष हुआ।
- 8,010 करोड़ रुपए की लाभांश दायिता का पूर्ण रूप से भुगतान किया गया।
- रेलवे ने योजनागत वित्तपोषण के लिए 2013-14 में 11,710 करोड़ रुपए के आंतरिक संसाधन सृजित किए।
- 93.5% संशोधित अनुमानों में परिचालन अनुपात में 2.7% की कमी आई।

बजट अनुमान 2014-15

- 1101 मिलियन टन माल का लदान, जो 2013-14 के मुकाबले 51 मिलियन टन अधिक रहेगा।
- यात्री यातायात में वृद्धि - 2%
- मालभाड़ा आमदनी - 1,05,770 करोड़ रुपए।
- यात्री आमदनी - 44,645 करोड़ रुपए, बढ़ाए गए मासिक सीज़न टिकट किरायों को वापस लेने पर 610 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा।
- कुल प्राप्तियां - 1,64,374 करोड़ रुपए; कुल व्यय - 1,49,176 करोड़ रुपए;
- 28,850 करोड़ रुपए का पेंशन अनुमान
- 9,135 करोड़ रुपए का अनुमानित लाभांश भुगतान।
- परिचालन अनुपात 92.5% रखा गया है जो 2013-14 की तुलना में अधिक है।

वार्षिक योजना 2014-15

- 65,445 करोड़ रुपए का अब तक का उच्चतम योजना परिव्यय
  - सकल बजटीय समर्थन -30,100 करोड़ रुपए
  - रेलवे संरक्षा निधि -2,200 करोड़ रुपए
  - आंतरिक संसाधन -15,350 करोड़ रुपए
  - ईबीआर-बाजार से ऋण -11,790 करोड़ रुपए
  - ईबीआर-पीपीपी -6,005 करोड़ रुपए
- बजटीय संसाधनों के अंतर्गत योजना परिव्यय 47,650 करोड़ रुपए रखा गया है जो 2013-14 के मुकाबले 9,383 करोड़ रुपए अधिक है- उच्चतर योजना परिव्यय संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए है।
- वर्ष के दौरान पूरी होने वाली लक्षित परियोजनाओं को पूर्ण वित्तीय परिव्यय।
- समय पर पूरा करने केलिए 30 प्राथमिकता कार्यों को पर्याप्त आबंटन किया गया।

दूरस्थ क्षेत्रों पूर्वोत्तर, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के लिए परियोजनाएं

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही 23 परियोजनओं जिनमें 11 राष्ट्रीय परियोजनाएं शामिल हैं, के लिए 5,116 करोड़ रुपए की राशि अलग से निर्धारित की गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 54% अधिक है।
- राष्ट्र को समर्पित उधमपुर-कटरा रेल संपर्क के उधमपुर-बनिहाल भाग को बस से जोड़ने के लिए जम्मू एवं कश्मीर के साथ समझौता किया जाना है ताकि यात्री अपने प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक एक ही टिकट से श्रीनगर आसानी से पहुँच सके।
- बनिहाल से कटरा के बचे हुए रेल संपर्क के कार्य को पूरा करने के लिए ध्यान देना।
- इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में 20,680 करोड़ रुपए की लागत वाली 29 परियोजनाएं चल रही हैं।
- समन्वय संबंधी आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर रेलवे तथा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के अधिकारियों की एक समिति गठित करना।

नए सर्वेक्षण

- नई लाइनों के 18 सर्वेक्षण।
- दोहरीकरण, तीसरी तथा चौथी लाइन एवं आमान परिवर्तन के 10 सर्वेक्षण।

गाड़ियां

- 5 नई जनसाधारण गाड़ियां शुरू की जाएंगी।
- 5 प्रीमियम तथा 6 एसी गाड़ियां शुरू की जाएंगी।
- 27 नई गाड़ियां शुरू की जाएंगी।
- 8 नई यात्री गाड़ियां, 5 डेमू सेवाएं तथा 2 मेमू सेवाएं शुरू की जाएंगी तथा 11 गाड़ियों का विस्तार किया जाएगा।

******